

संधारणीय भारत के लिये इथेनॉल मशिरण

यह एडटोरियल 21/01/2025 को बज़िनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “[**Blending dilemma: Conflicting priorities on flex-fuel need clear policy**](#)” पर आधारित है। यह लेख भारत के इथेनॉल-मशिरण कार्यक्रम को संवहनीयता, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और कारबन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने लाता है। हालाँकि, फीडस्टॉक की कमी, जल-गहन उत्पादन और आपूरति शृंखला की अक्षमताओं जैसी चुनौतियों से नीति सिमरथन एवं नवाचार के माध्यम से नपिटने की आवश्यकता है।

प्रलिमिस के लिये:

भारत का इथेनॉल-मशिरण कार्यक्रम, बदिशी मुद्रा, PM-JI-VAN योजना, राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मशिन, भारतीय खाद्य निगम, वैश्वकि जैव ईंधन गठबंधन, राष्ट्रीय हरति गतशीलता रणनीति, FCI, इलेक्ट्राकि वाहनों का तीव्र अंगीकरण और वनिस्माण, न्यूनतम समरथन मूल्य, PM कृषि सिवाई योजना

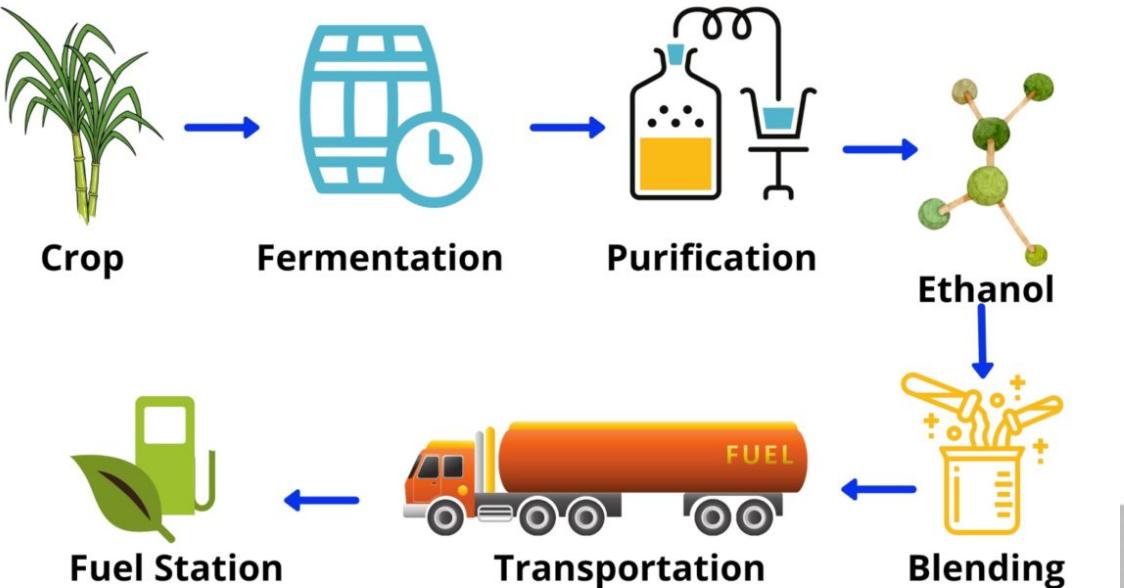
मेन्स के लिये:

भारत के लिये इथेनॉल मशिरण के प्रमुख लाभ, भारत में इथेनॉल मशिरण से जुड़े प्रमुख मुद्दे।

भारत का इथेनॉल-मशिरण कार्यक्रम संवहनीयता, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और कारबन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, 1.1 ट्रलियन रुपए की [बदिशी मुद्रा](#) की बचत की है और 50 मतियन टन CO₂ उत्सर्जन को रोका है। हालाँकि, फीडस्टॉक की कमी, जल-गहन इथेनॉल उत्पादन, आपूरति शृंखला की अक्षमताएँ और मूल्य निर्धारण संबंधी चिताएँ सहति चुनौतियों बनी हुई हैं। नीति सिमरथन, बुनियादी ढाँचे के वसितार और तकनीकी नवाचार के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करना इस संबंध में प्रगति को गतिदेने के लिये महत्वपूर्ण है।

इथेनॉल सम्मशिरण क्या है?

- इथेनॉल सम्मशिरण के बारे में: इथेनॉल, जो कपिादप आधारित स्रोतों से प्राप्त एक जैव ईंधन है, को पेट्रोल के साथ मिलाकर अधिक संधारणीय और स्वच्छ ईंधन बनाने की प्रक्रिया को इथेनॉल सम्मशिरण कहा जाता है।
 - इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है, कारबन उत्सर्जन कम होता है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।
 - भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः गन्ना, गुड़, मक्का, चावल और अन्य बायोमास स्रोतों से किया जाता है।
 - भारत सरकार ने परविहन ईंधन में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2003 में [इथेनॉल मशिरति पेट्रोल \(EBP\)](#) कार्यक्रम शुरू किया था।
- इथेनॉल मशिरण के लिये सरकारी पहल:
 - **PM-JI-VAN योजना** - कृषि अपशिष्ट से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन को समर्थन देती है।
 - **राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम** - संधारणीय ऊर्जा के लिये इथेनॉल और अन्य जैव ईंधन को बढ़ावा देता है।
 - **ब्याज अनुदान योजना** - इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
 - **GST में कमी** - EBP कार्यक्रम के लिये इथेनॉल पर 5% कर लगाया गया (18% से घटाकर) ताकि इसे अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
- वर्तमान स्थिति और भविष्य का रोडमैप: वर्ष 2022 तक 10% सम्मशिरण का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया, जिससे वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मशिरण (E20) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त हो गया।
 - वर्तमान में, वर्ष 2024 तक इथेनॉल सम्मशिरण 15% है। इथेनॉल-समरपति ईंधन स्टेशनों और E20-संगत वाहनों का वसितार कार्यान्वयन में तेज़ी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।



भारत के लिये इथेनॉल सम्मिश्रण के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- उत्तराखण्ड और आयात पर नियन्त्रिता में कमी: भारत अपनी [कच्चे तेल की](#) जरूरतों का 87% से अधिक आयात करता है, जिससे यह मूल्य असंविधानीयता और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
 - इथेनॉल सम्मिश्रण आयातित पेट्रोल के स्थान पर घरेलू स्तर पर उत्पादित [जैव ईंधन](#) का उपयोग करके इस नियन्त्रिता को कम करता है, जिससे उत्तराखण्ड में आत्मनियन्त्रिता बढ़ती है।
 - इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम से पछिले दशक में पहले ही 1.1 ट्रिलियन रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है।
 - इसके अतिरिक्त, इथेनॉल सम्मिश्रण से वर्ष 2014 और वर्ष 2024 के दौरान 181 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रतिस्थिरपक्षि करने में मदद मिली।
- कारबन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी: वाहनों से होने वाला उत्सर्जन शहरी वायु प्रदूषण और जलवायु परविरतन में प्रमुख योगदानकर्ता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ एवं प्रदूषण क्षरण बढ़ रहा है।
 - इथेनॉल में ऑक्सीजन अणु होते हैं जो अधिक पूरण दहन को संभव बनाते हैं तथा कारबन मोनोऑक्साइड और कणिका पदारथ उत्सर्जन को कम करते हैं।
 - [राष्ट्रीय जैव-उत्तराखण्ड मिश्रण](#) जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ वकिलप के रूप में इथेनॉल को बढ़ावा देता है, जो भारत के नेट-ज़ीरो वर्ष 2070 लक्ष्य के अनुरूप है।
 - वर्ष 2014 से अब तक इथेनॉल कार्यक्रम ने CO₂ उत्सर्जन में 544 लाख मीट्रिक टन की कटौती की है, जिससे वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।
- आरथिक विकास और ग्रामीण रोजगार: इथेनॉल उत्पादन [गनना](#), मक्का और अन्य जैव ईंधन फसलों के माध्यम से कसिनों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अरथव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
 - इथेनॉल की बढ़ती मांग से डिस्टिलरी और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में नविश को बढ़ावा मिलता है, जिससे रोजगार सृजन होता है तथा संकटपूरण प्रवास में कमी भी आती है।
 - [PM-JI-VAN](#) योजना सेकंड जेनरेशन के इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिससे ग्रामीण अरथव्यवस्था को और भी मजबूती मिलती है।
 - इथेनॉल सम्मिश्रण से कसिनों को ₹87,558 करोड़ और डिस्टिलरिस को ₹1,45,930 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे ग्रामीण रोजगार एवं कृषि-औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला।
- फसल पद्धतियों में विविधता और अपशिष्ट उपयोग: इथेनॉल उत्पादन चावल और गेहूँ जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर मक्का एवं जैव वैकल्पिक खाद्य पदारथों की ओर संकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे संधारणीय कृषि को बढ़ावा मिलता है।
 - सरकार ने [भारतीय खाद्य नियम \(FCI\)](#) को इथेनॉल उत्पादन के लिये चावल और मक्का की अनुमति दी है, जिससे कसिनों की सतत आय सुनिश्चित होगी।
 - मक्का से प्राप्त इथेनॉल की कीमत 51.55 रुपए प्रति लीटर है और FCI चावल से प्राप्त इथेनॉल की कीमत 56.87 रुपए प्रति लीटर है जिससे अधिकृत अनाज का उपयोग आरथिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है।
 - ब्याज अनुदान योजना ने अनाज आधारित डिस्टिलरी में नविश आकर्षित किया है, जिससे इथेनॉल की आपूरति को बढ़ावा मिला है।
- विदेशी नविश और औद्योगिक विकास: भारत के इथेनॉल प्रोत्साहन ने जैव ईंधन अवसंरचना में निजी नविश के लिये एक आकर्षक बाज़ार का सृजन किया है, जो घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की पूँजी को आकर्षित कर रहा है।
 - दीर्घकालिक इथेनॉल खरीद नीति जैसी नीतियाँ राजस्व दृश्यता प्रदान करती हैं तथा डिस्टिलरी और आपूरति शृंखलाओं में बढ़े पैमाने पर

नविश को प्रोत्साहिति करती हैं।

- **G20 शिखिर सम्मेलन वर्ष 2023** में शुरू किये गए **वैश्वकि जैव ईंधन गठबंधन (GBA)** ने भारत को इथेनॉल व्यापार और प्रौद्योगिकी में वैश्वकि अग्रणी के रूप में स्थापिति किया है।
- इथेनॉल उद्योग के तीव्र वस्तिर से **40,000** करोड़ रुपए का नया नविश हुआ है, जिससे भारत की वनिरिमाण और नरियात कषमता बढ़ी है।
- **ऑटोमोबाइल और ईंधन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:** उच्च इथेनॉल मशिरण के लिये वाहन प्रौद्योगिकी और ईंधन वितरण नेटवर्क में प्रगति की आवश्यकता है, जिससे भारत के ऑटो क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
 - वाहन नरिमाना **E20-अनुरूप ईंजन** विकसित कर रहे हैं, जिससे इथेनॉल-पेट्रोल मशिरण में दक्षता और स्थायत्व सुनिश्चित हो सके।
 - अप्रैल 2024 तक **E20 पेट्रोल 13,569 PSU** आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा। यह पूरे भारत में इथेनॉल मशिरण के वसितार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 - यह परिवर्तन **राष्ट्रीय हरति गतशीलता रणनीति** का समर्थन करता है, जो बहु-ईंधन भविष्य के लिये इथेनॉल को EV और हाइड्रोजन ईंधन के साथ एकीकृत करता है।

ETHANOL AS A FUEL



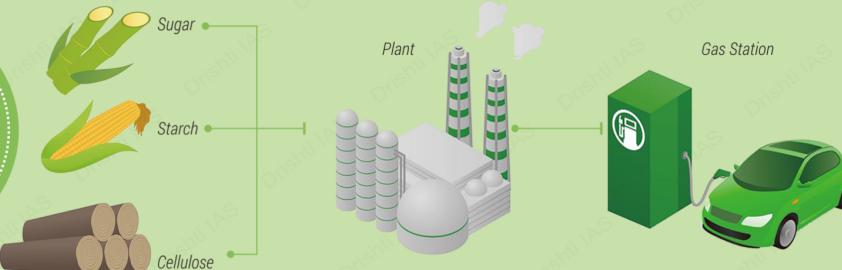
About Ethanol

- One of the principal biofuels
- Also called ethyl alcohol (C₂H₅OH)

Produced

- Naturally by fermentation of sugar (or corn, rice etc)
- By petrochemical processes (ethylene hydration)

World Biofuel Day is celebrated on 10 August to raise awareness about the importance of non-fossil fuels.



Ethanol Blending

Blending ethanol with petrol to burn less fossil fuel while running vehicles.

Blending Target

- 20% ethanol blending in petrol (E20) by 2025
- Currently, ethanol makes up 10% of the petrol used in vehicles.

Challenges in Success

- High land requirement for sugarcane (+ consequent food prices issue)
- High water requirement of biofuel crops

Significance

- Reduce oil imports
- Equivalent efficiency at a lower cost than petrol
- Burns completely and cleaner than petrol
- Ethanol produced from farm residue to boost farmers' income

Related Initiatives

- Roadmap for Ethanol Blending in India (Report by NITI Aayog) (2021)
- E100 Pilot Project (Network for production and distribution of ethanol) (2021)
- Pradhan Mantri JI-VAN Yojana (to boost 2G ethanol projects) (2019)
- The National Policy on Biofuels (2018)

भारत में इथेनॉल सम्मशिरण से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **इथेनॉल उत्पादन की जल-गहन प्रकृति:** भारत में इथेनॉल उत्पादन बहुत हद तक गन्ने पर निर्भर है, जिसके लिये भारी मात्रा में जल संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे पहले से ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की कमी और भी बढ़ जाती है।
 - इससे, वैश्व रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, असंवहनीय कृषिपद्धतियों एवं भूजल की कमी के बारे में चिताएँ उत्पन्न होती हैं।
 - **मक्का और ज्वार** जैसे वैकल्पिक फीडस्टॉक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कम इथेनॉल उत्पादन और कसिानों की प्राथमिकताओं के कारण उनका उपयोग सीमित है।
 - **NITI आयोग** के अनुसार, गन्ना और धान दोनों ही देश के सचिर्वार्ष जल का 70% उपयोग करते हैं, जिससे इथेनॉल की दीर्घकालिक संवर्हनीयता के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- **खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीतिपर प्रभाव:** जैसे-जैसे इथेनॉल की मांग बढ़ती है, चावल और मक्का जैसे खाद्यान्नों का अधिक उपयोग ईंधन के

लयि कथिया जाता है, जसिसे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं तथा खाद्य सुरक्षा प्रभावति हो सकती है।

- इथेनॉल उत्पादन के लयि **FCI** चावल और मक्का के उपयोग से अधिशेष बफर स्टॉक में कमी आ सकती है, जसिसे कमी के दौरान खाद्य कीमतों को स्थरि रखने की सरकारी क्षमता सीमित हो सकती है।
 - इससे ऊर्जा के लयि खाद्यान्नों के उपयोग को लेकर नैतिक चतिएँ उत्पन्न होती हैं, जबकि भारत में कृपोषण एक चुनौती बनी हुई है।
- **FAO रपोर्ट-2023** में चेतावनी दी गई है कि जैव ईंधन के वसितार से वैश्वकि खाद्य आपूरति शृंखलाएँ कड़ी हो सकती हैं, जसिसे कमज़ोर आबादी प्रभावति होगी।
- सीमित इथेनॉल उत्पादन क्षमता और आपूरति शृंखला की अड़चनें: तीव्र विकास के बावजूद, भारत का इथेनॉल उत्पादन और वतिरण बुनियादी कार्यदाँचा वर्ष 2025 तक 20% मशिरण लक्षण को पूरा करने के लयि अप्रयाप्त है।
 - परविहन चुनौतियों और भंडारण बाधाओं सहित आपूरति शृंखला की अकुशलताएँ सभी क्षेत्रों में समान इथेनॉल उपलब्धता को कठनि बना देती हैं।
 - कई राज्यों में प्रयाप्त डिस्ट्रिलरी और मशिरण सुवधियों का अभाव है, जसिके कारण उन्हें अन्य राज्यों से इथेनॉल आयात पर निभर रहना पड़ता है।
- प्रौद्योगिकी और वाहन अनुकूलता चुनौतियाँ: भारत का वाहन बेड़ा मुख्यतः **E10** ईंधन के लयि डिजिइन कथिया गया है, तथा **E20** और उससे आगे के ईंधन पर परविरतन के लयि इंजन डिजिइन तथा ईंधन प्रणालियों में संशोधन की आवश्यकता है।
 - इथेनॉल की उच्च मात्रा से संक्षण हो सकता है और ईंधन दक्षता कम हो सकती है, जसिसे उपभोक्ताओं के लयि दीर्घकालिक प्रबंधन में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
 - ऑटोमोबाइल निभाता **E20**-संगत इंजन पर काम कर रहे हैं, लेकनि मौजूदा वाहनों को रेट्रोफटि कथिया जाने तक प्रदर्शन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- वतितीय व्यवहार्यता और मूल्य असंवहनीयता: गनना और अनाज उत्पादन में परविरतनशीलता के कारण इथेनॉल उत्पादन मूल्य में उत्तार-चढ़ाव के अधीन है, जसिसे उद्योग की लाभप्रदता और नविश संवहनीयता प्रभावति होती है।
 - डिस्ट्रिलरी कंपनियों सरकार द्वारा निरधारित खरीद मूल्यों पर निभर रहती है, जो हमेशा बाज़ार की गतशीलता के अनुरूप नहीं होते, जसिसे नविशकों के लयि अनश्चितिता उत्पन्न होती है।
 - इथेनॉल की ऊर्जा सामग्री गैसोलीन की तुलना में कम है, जसिसे समान माइलेज के लयि अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जसिसे उपभोक्ताओं के लयि लागत लाभ की भरपाई हो सकती है।
- इथेनॉल उत्पादन में प्रयावरण संबंधी चतिएँ: जबकि इथेनॉल वाहनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया, वशिष रूप से गनने व गुड़ से अधिक जल उपयोग, निविनीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट उत्सर्जन को बढ़ावा देती है।
 - इथेनॉल डिस्ट्रिलरी से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल नकिलता है। इस अपशिष्ट जल को वनिसे के नाम से जाना जाता है, जसिसे कार्बनकि पदार्थ, अवशिष्ट शरकार और अन्य प्रदूषकों की उच्च सांदरता होती है।
 - यदि इसका उच्चति उपचार नहीं कथिया गया तो इससे गंभीर प्रयावरणीय खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें जल प्रदूषण और जलीय पारस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की कमी शामलि है।
- सरकारी सब्सिडी पर भारी निभरता: भारत में इथेनॉल उत्पादन ब्याज अनुदान योजनाओं, वभेदक मूल्य निरधारण और कर छूट सहित सरकारी प्रोत्साहनों पर बहुत अधिक निभर है।
 - कसी भी नीतिगत बदलाव या वतितीय सहायता में कमी से डिस्ट्रिलर्स और कसिनों के लयि इथेनॉल उत्पादन आरथकि रूप से अव्यवहारकि हो सकता है।
 - दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल को बढ़ावा देने के लयि परधानमंत्री JI-VAN योजना को सत्र 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, लेकनि उच्च पूंजीगत लागत के कारण इसके अंगीकरण की गति धीमी है।
 - इथेनॉल सम्मशिरण लक्ष्यों में नीतिगत उत्तार-चढ़ाव, जैसे कविरेष 2030 से 2025 तक का परविरतन, उद्योग के हतिधारकों के लयि कार्यान्वयन चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

इथेनॉल सम्मशिरण को मज़बूत करने और कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लयि क्या उपाय कथिया जाएंगे?

- गनने से परे फीडस्टॉक विधीकरण का वसितार: इथेनॉल के लयि गनने पर निभरता संधारणीय नहीं है; भारत को वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में मक्का, ज्वार, बांस और कृषि अपशिष्ट को बढ़ावा देना चाहियि।
 - बेहतर अनुसंधान एवं विकास वतितपोषण के साथ प्रधानमंत्री जी-वन योजना को मजबूत करने से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन में तेज़ी आ सकती है।
 - सरकार को जैव ईंधन फसलों की ओर रुख करने वाले कसिनों को वतितीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लयि **PM-कसिन योजना** को भी एकीकृत करना चाहियि।
 - क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों और नगरपालकिए अपशिष्ट से इथेनॉल उत्पादन का वसितार करने से इसकी उपलब्धता और बढ़ सकती है।
 - इथेनॉल से जुड़ी फसलों के लयि एक संरचति न्यूनतम समर्थन मूल्य (**MSP**) कार्यदाँचा स्थरि कर्ये माल की आपूरति सुनिश्चिति कर सकता है।
- ग्रामीण आसवनयों और वकिंदरीकृत उत्पादन को सुदृढ़ बनाना: ग्रामीण क्षेत्रों में लघु-स्तरीय आसवनयों के साथ वकिंदरीकृत इथेनॉल उत्पादन मॉडल से आपूरति शृंखला दक्षता में सुधार हो सकता है और परविहन लागत में कमी आ सकती है।
 - इथेनॉल इकाइयों को **FPO** (कसिन उत्पादक संगठनों) के साथ जोड़ने से स्थानीय कसिन सशक्त हो सकते हैं तथा फीडस्टॉक की प्रत्यक्ष खरीद बढ़ सकती है।

- सरकार को छोटे उद्यमियों को इथेनॉल संयंत्र स्थापति करने के लिये मुद्रा योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना चाहयि।
- अनाज उत्पादक राज्यों में जैव-रफिअनरी क्लस्टर स्थापति करने से कृषेत्रीय इथेनॉल उपलब्धता में संतुलन आएगा।
- **वाहन अनुकूलता और ईंधन अवसंरचना में वृद्धि:** वर्ष 2025 तक E20-संगत वाहनों को अनविार्य बनाने के साथ -साथ उपभोक्ताओं की नाराजगी से बचने के लिये पुराने वाहनों को पुनः उपयोग में लाने के लिये प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहयि।
- ऑटोमोबाइल नरिमाताओं और IT के साथ मलिकर लागत परभावी इंजन संशोधन विकासित करने से यह बदलाव आसान हो सकता है।
- पूरे भारत में, वशिष्ठकर गैर-गन्ना उत्पादक राज्यों में, इथेनॉल-समर्पण ईंधन पंपों का विस्तार करने से एक समान पहुँच सुनिश्चित होगी।
- सार्वजनिक परविहन परणालयों में इथेनॉल-मशिरति ईंधन का उपयोग अनविार्य किया जाना चाहयि, तथा हाइब्रडि समाधानों के लिये जैव ईंधन नीतियों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अपनाने और वनिरिमाण (FAME) को एकीकृत किया जाना चाहयि।
- **मूल्य संवहनीयता और बाजार-संबद्ध खरीद में सुधार:** इथेनॉल उत्पादकों को कच्चे माल की कीमतों में उत्तार-चढ़ाव से बचाने के लिये एक गतिशील इथेनॉल मूल्य स्थरिकरण कोष बनाया जाना चाहयि।
 - विद्युत कषेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) के समान, बाजार संचालन इथेनॉल खरीद तंत्र की ओर बढ़ने से नजी विद्युत कषेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।
 - इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी कारबन क्रेडिट प्रणाली हरति ईंधन अपनाने वाले उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।
 - फसल उपज और कच्चे तेल की कीमतों में मौसमी बदलावों के आधार पर लचीले मूल्य नियंत्रण तंत्र से इथेनॉल उत्पादन को अधिक प्रूर्वानुमानित बनाया जा सकता है।
- **इथेनॉल उत्पादन में जल संवहनीयता को संबोधति करना:** PM कृषि स्थिरता योजना के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से जल-कुशल जैव ईंधन फसलों की ओर सुख करने से इथेनॉल उत्पादन में अत्यधिक जल की खपत को कम किया जा सकता है।
 - इथेनॉल से जुड़ी फसलों के लिये ड्रपि स्थिरता और सूक्ष्म स्थिरता प्रणालयों को बढ़ावा देने से संवहनीयता बढ़ेगी।
 - इथेनॉल संयंत्रों को शून्य-तरल उत्सर्जन (ZLD) प्रणाली लागू करने के लिये प्रोत्साहन करने से औद्योगिक जल प्रदूषण में कमी आ सकती है।
 - नमामिगंगे के अंतर्गत अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं के साथ इथेनॉल संयंत्रों को एकीकृत करके ज़मिमेदार जल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **नविश और नजी विद्युत की भागीदारी में तेज़ी लाना:** कर प्रोत्साहन के साथ एक समर्पण इथेनॉल अवसंरचना विकास कोष इथेनॉल संयंत्रों में नजी नविश को आकर्षित कर सकता है।
 - इथेनॉल उत्पादन को मेक इन इंडिया के साथ जोड़ने से डिस्ट्रिली उपकरणों और ईंधन योजकों के घेरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा मिल सकता है।
 - व्यवहार्यता अंतर वित्तीय प्रणाली (VGF) को गैर-पारंपरिक जैव ईंधन राज्यों में नजी इथेनॉल संयंत्रों तक बढ़ाया जाना चाहयि।
 - जैव ईंधन अनुसंधान एवं वितरण में एफडीआई अवसरों के विस्तार से वैश्वकिविशिष्टता और पूँजी आएगी।
 - इथेनॉल रसद और वितरण में सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP) को सक्षम करने से देशव्यापी आपूरत विकास में वृद्धि होगी।
- **नीतिसमन्वय और शासन कार्यदांबिकों को मज़बूत करना:** राज्य सरकारों को नविश आकर्षित करने के लिये इथेनॉल-विशिष्ट औद्योगिक नीतियाँ शुरू करने के लिये प्रोत्साहन किया जाना चाहयि।
 - अंतर्राज्यीय इथेनॉल परविहन विनियमों को मज़बूत करने से रसद संबंधी व्यवधानों और मूल्य असमानताओं को रोका जा सकेगा।
 - इथेनॉल संयंत्र अनुमोदन के लिये एकल खड़की मंजूरी प्रणाली से नौकरशाही संबंधी देरी कम हो जाएगी।
 - इथेनॉल मशिरति पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन के साथ जोड़ने से दीर्घकालिक स्वच्छ ईंधन रोडमैप तैयार हो सकता है।

निषिकरण:

भारत की इथेनॉल-मशिरण पहल में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कारबन उत्सर्जन को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं। हालाँकि, वर्ष 2025 तक 20% मशिरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये फीडस्टॉक की कमी, जल के उपयोग और बुनियादी अवसंरचना की सीमाओं जैसी चुनौतियों पर काबू पाना महत्वपूरण है। नीतिसमर्थन को मज़बूत करना, विकेंद्रीकृत उत्पादन का विस्तार करना तथा वाहन अनुकूलता में सुधार करना प्राप्ति को गति प्रदान करेगा।

प्रश्नोत्तर:

भारत की ऊर्जा रणनीति में इथेनॉल मशिरण के महत्व पर चर्चा कीजिये। इसके कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएँ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. चार ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिये गए हैं। उनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिये की जा सकती है? (वर्ष 2010)

- (A) जटरोफा
- (B) मक्का
- (C) पौगामयि

(D) सूरजमुखी

उत्तर: (B)

प्रश्न. जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए नमिन में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? (वर्ष 2020)

1. कसावा
2. गेहूँ के टूटे दाने
3. मूँगफली के बीज
4. चने की दाल
5. सड़े हुए आलू
6. मीठे चुकंदर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1, 2, 5 और 6
(B) केवल 1, 3, 4 और 6
(C) केवल 2, 3, 4 और 5
(D) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (A)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ethanol-blending-for-sustainable-india>

